NLU Meghalaya launches moot court contest

https://timesofindia.indiatimes.com/city/shillong/nlu-meghalaya-hosts-1st-moot-court-contest-in-collaboration-with-nhrc/articleshow/108571552.cms

Shillong: The National Law University (NLU) Meghalaya inaugurated its 1st Moot Court Competition, organised in collaboration with **National Human Rights Commission**, at its campus here on Friday, reports Manosh Das.

“The competition drew law students from across the country, spotlighting high-level debates on crucial human right issues,” a National Law University spokesperson said.

We also published the following articles recently

North Korean defectors share human rights violations in country at United Nations: ReportNorth Korean defectors recount harrowing experiences at the UN event in Geneva, urging for stronger action against human rights violations in their home country. The EU is leading a motion to uncover crimes against humanity in North Korea, supported by US ambassador Michele Taylor.108541608

No maintenance from in-laws under CrPC Sec 125: Karnataka high courtKarnataka high court ruled against daughter-in-law's maintenance claim under Section 125 of CrPC, quashing the Ballari court's order for monthly payments. The court upheld the law allowing wives and parents to claim maintenance.108377975

UP law against conversion covers live-in ties too: Allahabad high courtAllahabad HC applies UP's 2021 anti-conversion law to live-in partners, like married interfaith couples. Ordered registration for a couple married through Arya Samaj rituals. Protection plea dismissed due to non-compliance with law.108474086

NHRC issues notice to WB government over human rights violation and eco-tourism in Sundarbans

https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Mar/17/nhrc-issues-notice-to-wb-government-over-human-rights-violation-and-eco-tourism-in-sundarbans

The petitioner sought NHRC's intervention on the major Human rights violation in Sundarbans due to inaccessible social welfare schemes and its politicization, human tracking, rampant man-animal conflict.

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Chief Secretary, government of West Bengal to submit an action taken report on the violation of human rights and degradation of environment mixed with eco-terrorism in Sundarbans area.

The NHRC has taken cognizance of the petition filed by Supreme Court lawyer and noted human rights activist, Radhakanta Tripathy.

The petitioner sought for the intervention of the NHRC on the major Human Rights violation in Sundarbans region due to inaccessible social welfare schemes and its politicization, human tracking, rampant man-animal conflict.

The petition highlighted the issues of tribal land alienation, lack of basic amenities to the inhabitants, lack of bare necessities, violation of constitutional safeguard, especially to the schedule tribes and other vulnerable strata of society, non compliance of statutory provisions including financial irregularities in implementation of projects in the area.

The petition contended high rates of child marriages, malnutrition, distress migration, Communication problems including all weather roads, crossing water bodies and digital communication, lack of education and health care, potable drinking water etc. in the Sundarbans region.

The area records highest mortality rate of children drowning across the globe. The Tiger widows and the death of sole bread winners due to Man-Animal conflict lead miserable life sans State Support.

Stating failure of the State in preservation of bio diversity, protection of environment., Tripathy stated increasing trend of eco-terrorism in the area.

Suggesting certain measures to tackle the menace, hardships faced in the area, Tripathy has requested for investigation done independently and impartially in a timely manner, so that the sacrosanct rights of every individual can be protected in the poverty stricken people of Sundarbans.

He also requested for regular follow up with field visit by a team of officials of the NHRC, investigation by its Special Rapporteur, Special monitor.

Tripathy, who has been fighting for the cause of residents of Sundarbans since 2017, said the Government declares Plans and Schemes worth Hundreds of Crores Rupees for Sundarbans but due to lack of proper implementation the Problems of Human Rights violation continues.

Human rights defenders and whistle blowers are attacked and threatened in the area. Seeking permanent solution of the issue of human rights in Sundarbans, a world heritage site, Tripathy contended that the residents of the region have been deprieved of their basic human rights for decades despite media coverage, towering claims by consecutive Governments and memorandums submitted by the victims to the State Authorities.

Despite the Government of West Bengal has set up Sundarban Affairs Department since the year 1994, spreading over 16 Police Stations and 19 Panchayat Samities of South and North 24-Parganas districts, the human rights and environment problems still persist.

The NHRC in its order stated “Let a copy of the complaint be transmitted to the Chief Secretary, Govt. of West Bengal, Kolkata, through online mode, to ensure the needful action and submit an action taken report to the Commission within four weeks.”

Eco-terrorism’ is a phenomenon of violence to the ecology and environment, which disturb the harmony and balance between the natural and the manmade and endangers life. It cause great danger to the health and well being of the existing mass and also the generations to come.

धर्मशाला : NHRC मॉनिटर ने लाला लाजपत राय मुक्त सुधारगृह में व्यवस्थाओं का लिया जायजा

https://mbmnewsnetwork.com/himachal-pradesh/662191/%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-nhrc-%E0%A4%AE%E0%A5%89%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE

धर्मशाला, 17 मार्च : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के विशेष मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने अपने ज़िला कांगड़ा प्रवास के दौरान आज रविवार को लाला लाजपत राय ज़िला एवं मुक्त सुधारगृह का दौरा किया और यहां क़ैदियों को दी जा रही सुविधाओं तथा उनके लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कैदियों से अच्छा बर्ताव करने और उनकी शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के निर्देश दिए।

जेल अधीक्षक विकास भटनागर, सीडीपीओ रमेश जागवान और कारागृह के अन्य कर्मचारियों के साथ गोयल ने विभिन्न बैरकों की भी जांच की। उन्होंने मुक्त सुधारगृह के तहत कैदियों के लिए स्थापित विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों का भी दौरा किया। उन्होंने मुक्त सुधारगृह के तहत कैदियों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

गोयल ने महिला विंग, रसोई घर और वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विचाराधीन कैदियों और कैदियों से चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की और प्रशासन को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिये।

गोयल ने कहा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए एनएचआरसी द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कैदियों से मुक्त चर्चा कर उनके सुझावों और समस्याओं को भी विस्तार से सुना तथा उन्हें सकारात्मक रहते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करने की बात कही।

अवैध कोयला कारोबार मे शामिल हैं मंत्री और विधायक

https://rashtriyakhabar.com/118511/

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : असम के बक्सा में आज कोयले से लदे कम से कम पांच ट्रक जब्त कर लिए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रकों में बिना किसी कागजी कार्रवाई के कोयला भरा हुआ था। ट्रकों को अवैध रूप से लादे जाने की विशिष्ट जानकारी के आधार पर जब्त किया गया था।

वे कथित तौर पर असम के शिवसागर से भूटान जा रहे थे। पकड़े गए ट्रकों को इस प्रकार पंजीकृत किया गया था – पीबी 29 एल 9792, एएस 01 पीसी 9529, एएस 02 ई 5827, एएस 04 बीसी 8607 और पीबी 13 एआर 7363। ट्रकों के ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

इस बीच, असम के 16 राजनीतिक दलों ने भाजपा के मंत्रियों और विधायकों पर असम और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस बीच, असम के 16 राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अवैध कोयला घोटाले का पैसा खर्च करेगी।

असम जातीय परिषद (एजेपी) ने मुख्य चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** को एक-एक याचिका सौंपी। असम में, नागरिक समाज समूह लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर राज्य में अवैध कोयला खनन की अनुमति देने का आरोप लगाते रहे हैं।

अब ये आरोप खुद भाजपा के किसी मंत्री और विधायक को घेर सकते हैं।मार्च 2024 के पहले सप्ताह में, कांग्रेस के सदस्यों ने पत्रकारों को आपत्तिजनक तस्वीरें वितरित कीं। इन तस्वीरों में एक केंद्रीय मंत्री सुनील कुमार गुरुंग के साथ अवैध खनन कार्यों में शामिल होने के आरोप में दिख रहे हैं।

राज्य भूविज्ञान और खनन निदेशालय के निदेशक ने 16 मार्च को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे एक गोपनीय पत्र में गुरुंग का नाम लिया था, जिसमें क्षेत्र में अवैध कोयला खनन की समस्या को चिह्नित किया गया था. हालांकि, असम जातीय परिषद (एजेपी) क्षेत्रीय पार्टी ने आरोप लगाया कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पुलिस, वन और प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कोयला खनन, विशेष रूप से रैट-होल खनन, जारी रहा, जबकि 2014 में एनजीटी द्वारा रैट-होल खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।

ज्ञापन में एजेपी अध्यक्ष लुरिनजुतक गोगोई और महासचिव जगदीश भुइयां ने कहा कि राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन के चलते हर महीने करीब 2,000 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन होने का अनुमान है. सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े कुछ राजनेताओं की भागीदारी असम में एक खुला रहस्य है। ये राजनेता अधिकारियों को कोयला निकालने के लिए व्यापारियों को प्रवेश पास जारी करने के लिए प्रभावित करते हैं।

एजेपी ने ज्ञापन में कहा कि राजनेताओं को क्षेत्र से बाहर निकलने वाले प्रत्येक ट्रक के लिए एक कट मिलता है और जबरन वसूली की गई राशि सरकारी अधिकारियों और घोटाले में शामिल प्रभावशाली राजनेताओं के उच्च अधिकारियों के साथ साझा की जाती है। इसके अलावा, अवैध रूप से खनन किए गए कोयले की भारी मात्रा का परिवहन पैसे के लेनदेन और कर चोरी के मामले में एक बड़ा मुद्दा है।

इस लेन-देन में करोड़ों रुपये शामिल हैं। यह एक बड़ा अवैध रैकेट है और सत्तारूढ़ दल के कुछ शक्तिशाली सदस्यों द्वारा सिंडिकेट संरक्षण है। यह जानकर हैरानी होगी कि रोजाना 500-600 ट्रक कोयले की ढुलाई (अकेले लेडो-मार्गेरिटा क्षेत्र में) की जा रही है और कमीशन की राशि 70,000 रुपये से 75,000 रुपये प्रति ट्रक है।